गुजरात राज्य

बनाम

नरेंद्र के. अमीन

13 अगस्त, 2007

[तरुण चटर्जी और पी. के. बालासुब्रमण्यन,जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 438-अग्रिम जमानत-अभियोजन की आशंका पर विचार किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई कि अभियुक्त को गवाहों को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा और उसकी अभिरक्षा में पूछताछ का अधिकार होना चाहिएः उचित नहीं-इसलिए, अग्रिम जमानत के आदेश ने इसे दरकिनार करने की सीमित सीमा तक हस्तक्षेप किया-सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।हत्या के एक मामले में, सत्र अदालत ने प्रतिवादी, एक पुलिस उपाधीक्षक को अग्रिम जमानत दे दी। अपीलार्थी-राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जांच के दायरे से परे जाकर एक ऐसे मामले पर विचार किया था जो लगभग बरी करने के आदेश को पारित करने जैसा प्रतीत होता था। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध सभी तथ्यों पर कोई उचित विचार नहीं किया

गया था और अपराध की गंभीरता, लेन-देन के आसपास की परिस्थितियों और प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई स्थिति को देखते हुए, यह अग्रिम जमानत से इनकार करने के लिए एक उपयुक्त मामला था; कि यह एक ऐसा मामला था जहां अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक थी और सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई आशंका को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि यदि प्रतिवादी को जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को पहले से दिए गए बयानों को वापस लेने और अभियोजन पक्ष को प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए प्रभावित करने और मजबूर करने की स्थिति में होगा।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1. यह आशंका कि प्रतिवादी जांच एजेंसी को प्रासंगिक जानकारी देने से बचने के लिए गवाहों को प्रभावित करने, प्रेरित करने या मजबूर करने की स्थिति में है, काल्पनिक नहीं माना जा सकता है और अदालत को अग्रिम जमानत देने से पहले उस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। अदालत को यह पता लगाने के लिए प्रतिवादी से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए था कि मृतक के साथ वास्तव में क्या हुआ या उसका अंत कैसे हुआ? इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन केवल इसे दरकिनार करने और अपीलार्थी की जमानत याचिका को

कानून के अनुसार और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने के बाद निचली अदालत द्वारा निपटा जाने के लिए छोड़ने की सीमित सीमा तक। यह कार्यप्रणाली न्याय और पूर्वाग्रह के हितों को भी कम करेगा। सत्र न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। (पैरा 5 और 6) (1012-बी-ई)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1065/2007

अतिरिक्त नगर सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 6, अहमदाबाद आपराधिक विविध मामले 2007 का आवेदन सं. 2019 में दिनांक 08.06.2007 के अंतरिम आदेश से।

अपीलार्थी के लिए K.T.S. तुलसी, रंजीत कुमार, हेमंतिका वाही, शिवांगी, पिंकी।

प्रतिवादी के लिए मिलन के. बनर्जी, ए. जी. आई., मोहन परासरन, ए. एस. जी., एच. रावल, सहायक एस. जी., गौरव अग्रवाल, सुषमा सूरी, शीला गोयल।

न्यायालय का आदेश पी. के. बालासुब्रमण्यन जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति दी गई

2. सोहराबुद्दीन शेख की कथित हत्या और उसकी पत्नी के लापता होने की जाँच की निगरानी करते हुए, 2007 की रिट याचिका (आपराधिक) 6 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की प्रार्थना करते हुए, विद्वान न्याय मित्र ने हमारे ध्यान में सत्र न्यायालय का एक आदेश लाया जिसमें पुलिस उपाधीक्षक डॉ. अमीन को अग्रिम जमानत दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि..... जब विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि गुजरात राज्य ने उस आदेश के खिलाफ अपील भी नहीं की है, तो गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय से उक्त आदेश को सीधे इस न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति मांगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय पहले से ही संबंधित अपराध से संबंधित मामले में था और उनके विचार में भी, आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता थी। इसके बाद, हमने गुजरात राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील को उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी। जब ऐसी याचिका, वर्तमान याचिका, दर्ज की गई थी, तो हमने प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुरोध के बावजूद नोटिस जारी किया, जो कैविएट पर उपस्थित हुए थे, उस नोटिस को जारी करने की आवश्यकता नहीं है और मामले की सुनवाई अंततः की जा सकती है। आज, हमने गुजरात राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान न्यायमित्र को सुना। 3.

गुजरात राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जांच के दायरे से परे यात्रा की है और उन्होंने मामले को इस तरह से निपटाया है कि यह लगभग बरी करने का आदेश पारित करने जैसा था। यह ठीक वही निवेदन था जो विद्वान न्यायमित्र ने पिछले दिन किया था, जिसने हमें इस याचिका पर सीधे इस न्यायालय में विचार करने के लिए प्रेरित किया। गुजरात राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध सभी तथ्यों पर कोई उचित विचार नहीं किया गया था और अपराध की गंभीरता, लेन-देन के आसपास की परिस्थितियों और प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई स्थिति को देखते हुए, यह अग्रिम जमानत से इनकार करने के लिए एक उपयुक्त मामला था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें हिरासत में पूछताछ जरूरी थी। सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई इस आशंका को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि यदि प्रतिवादी को जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को पहले से दिए गए बयानों को वापस लेने और अभियोजन पक्ष को प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए प्रभावित करने और मजबूर करने की स्थिति में होगा। जमानत देते समय अदालत ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

4. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने उत्तर में प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल संहिता की धारा 438 के तहत एक

आवेदन की जांच के लिए तैयार किए गए मापदंडों का पालन किया है और उनके द्वारा की गई टिप्पणियां उस जांच के संबंध में हैं और आदेश को लगभग बरी करने के आदेश के रूप में चिह्नित करना सही नहीं था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा केवल एक मामले में उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है और हाथ में मामले में, उपलब्ध परिस्थितियाँ और उपलब्ध सामग्री, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराती हैं। उन्होंने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देना उचित था। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें आक्षेपित आदेश के बाद, प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आदेश के अनुसार जमानत पर बढ़ा दिया गया है और उसने संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है और संहिता की धारा 439 के तहत आवेदन पर विचार करते हुए मामले को उस अदालत द्वारा तय करने के लिए छोड़ना उचित होगा।

5. हम सोचते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी द्वारा नियमित जमानत के लिए आवेदन संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है, हमारे लिए हमारे सामने पेश किए गए विभिन्न पहलुओं में जाना उचित नहीं होगा। फिर भी, हम सोचते हैं कि प्रतिवादी को अग्रिम जमानत देने में सत्र न्यायालय द्वारा किया गया दृष्टिकोण वांछित होने के लिए बहुत कुछ

छोड़ देता है। यह आशंका कि प्रतिवादी जांच एजेंसी को प्रासंगिक जानकारी देने से बचने के लिए गवाहों को प्रभावित करने, प्रेरित करने या मजबूर करने की स्थिति में है, काल्पनिक नहीं माना जा सकता है और अदालत को अग्रिम जमानत देने से पहले उस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। अदालत को यह पता लगाने के लिए प्रतिवादी से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए था कि कौसरबी के साथ वास्तव में क्या हुआ या उसका अंत कैसे हुआ? यह कहने के लिए पर्याप्त है कि परिस्थितियों में, हम प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन केवल इसे दरकिनार करने और अपीलार्थी की जमानत याचिका को कानून के अनुसार और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने के बाद निचली अदालत द्वारा निपटा जाने के लिए छोड़ने की सीमित सीमा तक। इस प्रकार, भले ही हम आदेश को अलग करते हैं, हम योग्यता के आधार पर प्रश्न में जाना और उस आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करना उचित नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि यह मार्ग न्याय और पूर्वाग्रह के हितों को भी कम करेगा। 6. इस प्रकार, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, प्रतिवादी को अग्रिम जमानत देने के अदालत के आदेश को दरकिनार करते हैं, लेकिन इस स्तर पर उस आवेदन को स्वीकार करना आवश्यक नहीं मानते हैं क्योंकि एक अर्थ में, उक्त आदेश ने खुद ही काम कर लिया है। हम सत्र न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह कानून के अनुसार संहिता की धारा 439 के तहत प्रतिवादी द्वारा जमानत

के लिए किए गए आवेदन पर विचार करे, उस आवेदन को हमारे सामने चुनौती दिए गए आदेश में निहित किसी भी चीज़ से पूरी तरह से अप्रभावित माने और इस आदेश में हमने जो कुछ भी कहा है उसे मुक्त कर रहे हैं।

अपील की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।